

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 266]

नई दिल्ली, बुधवार, अप्रैल 13, 2016/चैत्र 24, 1938

No. 266] NEW DELHI, WEDNESDAY, APRIL 13, 2016/ CHAITRA 24, 1938

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2016

सं. 22/2016- सेवा कर

सा.का.नि. 419(अ).—वित्त अधिनियम, 1944 (1944 का 32) की धारा 93 की उपधारा (1) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार, इस बात से संतुष्ट होते हुए कि ऐसा करना जनहित में आवश्यक है, एततद्वारा भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 25/2012-सेवाकर दिनांक 20 जून, 2012 जो कि भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग-II, खंड 3, उपखंड (i) में सा.का.नि. सं. 467(अ) के अंतर्गत दिनांक 20 जून, 2012 को प्रकाशित हुई थी, में एततद्वारा निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात:-

उक्त अधिसूचना में, प्रथम पैरा में-

- (i) प्रविष्टि 39 में "सरकारी प्राधिकरण" शब्दों के पहले "सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ;
- (ii) प्रविष्टि 53 के पश्चात निम्नलिखित प्रविष्टियां अंत:स्थापित की जाएंगी, अर्थात:-
- "54. सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा अन्य सरकार अथवा प्राधिकरण को प्रदान की जाने वाली सेवाएं : बशर्ते इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 घ के खंड (क) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं पर लागू नहीं होगी ;

1822 GI/2016 (1)

- 55. पासपोर्ट, वीजा, ड्राइविंग लाइसेंस, जन्म प्रमाणपत्र और मृत्यु प्रमाणपत्र जारी करने के माध्यम से सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं;
- 56. सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली ऐसी सेवाएं जिनमें ऐसी सेवाओं के लिए प्रभार्य सकल धनराशि 5 हजार रु से अधिक नहीं हो :

बशर्ते इस प्रविष्टि में निहित कोई भी बात वित्त अधिनियम 1994 की धारा 66 घ के खंड (क) के उपखंड (i), (ii) और (iii) में विनिर्दिष्ट सेवाओं पर लागू नहीं होगी:

बशर्ते यह कि यदि कराधान बिंदु नियम, 2011 के नियम 2 के खंड (ग) में यथा परिभाषित सेवा की निरंतर आपूर्ति सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाती है तो छूट केवल उन मामलों में लागू होगी जहां ऐसी सेवा के लिए प्रभार्य सकल धनराशि एक वित्त वर्ष में 5 हजार रु से अधिक नहीं हो;

- 57. सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा ऐसी संविदा के गैर-निष्पादन को सहन करने के माध्यम से दी जाने वाली सेवाएं जिनके लिए जुर्माने अथवा लिक्वीडेटेड नुकसान के रूप में प्रतिफल, इस संविदा के अंतर्गत सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण को देय है:
 - 58. सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा निम्नलिखित के माध्यम से प्रदान की जाने वाली सेवाएं:-
 - (क) इस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अपेक्षित पंजीकरण
- (ख) इस समय लागू किसी भी कानून के अंतर्गत अपेक्षित, कामगारों, उपभोक्ताओं अथवा आम जनता के सरंक्षण अथवा सुरक्षा से संबंधित परीक्षण, कैलीब्रेशन, सुरक्षा जांच-पड़ताल और प्रमाणन ;
- 59. कृषि के परियोजनों से किसी किसान द्वारा प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करने के लिए सौंपे गए अधिकार के माध्यम से सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं ;
- 60. संविधान के अनुच्छेद 243 जी के अंतर्गत पंचायत को सौंपे गए किसी कार्य के संबंध में किसी क्रियाकलाप के माध्यम से सरकार, स्थानीय प्राधिकरण अथवा सरकारी प्राधिकरण द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाएं;
- 61. किसी प्राकृतिक संसाधन का प्रयोग करने के लिए सौंपे गए अधिकार के माध्यम से सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं जिनमें प्रयोग करने का इस प्रकार का अधिकार सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा 01 अप्रैल, 2016 से पहले सौंपा गया था:

बशर्ते यह कि छूट केवल सेवाकर पर लागू होगी जो कि केवल एक बारगी प्रभार्य के रूप में ठीक अग्रिम अथवा किस्तों में, किसी प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग के अधिकार को सौंपे जाने के लिए देय होगा ;

- 62. किसी बीजनेस कारोबारी को वित्त वर्ष 2015-16 के दौरान लाइसेंस शुल्क के भुगतान अथवा स्पेक्ट्रम प्रयोगकर्ता प्रभार्य, जैसा भी मामला हो, के आधार पर दूर संचार सेवा प्रदाता के रूप में कार्य करने अथवा रेडिया आवर्ती स्पेक्ट्रम का प्रयोग करने की अनुमति देते हुए सरकार अथवा स्थानीय प्राधिकरण द्वारा प्रदान की गई सेवाएं;
- 63. मर्चेंट समयोपिर प्रभार्य के भुगतान पर आयात-निर्यात कर्गों के संबंध में निरीक्षण अथवा कंटेनर स्टिफिंग और ऐसी अन्य ड्यूटियों के लिए कार्यालय समय के पश्चात अथवा अवकाश के दिनों में अधिकारियों को तैनात करने के माध्यम से सरकार द्वारा प्रदान की गई सेवाएं।"

[फा. सं. 334/8/2016-टीआरयू] मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी:—प्रधान अधिसूचना सं. भारत के राजपत्र, असाधारण में अधिसूचना सं. 25/2012-सेवाकर दिनांक 20 जून, 2012 के अंतर्गत सा.का.िन. सं. 467(अ) दिनांक 20 जून, 2012 के तहत प्रकाशित की गई थी तथा इसमें अधिसूचना सं. 9/2016-सेवाकर दिनांक 01 मार्च, 2016 जो सा.का.िन. सं. 257(अ) दिनांक 01 मार्च, 2016 के तहत प्रकाशित की गई थी, में अंतिम बार संशोधन किया गया था।

MINISTRY OF FINANCE (DEPARTMENT OF REVENUE) NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2016

No. 22/2016-Service Tax

G.S.R.419(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 93 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government being satisfied that it is necessary in the public interest so to do, hereby makes the following further amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) No.25/2012-Service Tax, dated the 20th June, 2012, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 467 (E), dated the 20th June, 2012, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,-

- (i) in entry 39, after the words "Services by", the words "Government, a local authority or" shall be inserted;
- (ii) after entry 53, the following entries shall be inserted, namely:-
 - "54. Services provided by Government or a local authority to another Government or local authority:

 Provided that nothing contained in this entry shall apply to services specified in sub-clauses (i),(ii) and (iii) of clause (a) of section 66D of the Finance Act, 1994;
 - 55. Services provided by Government or a local authority by way of issuance of passport, visa, driving licence, birth certificate or death certificate;
 - 56. Services provided by Government or a local authority where the gross amount charged for such services does not exceed Rs. 5000/-:
 - Provided that nothing contained in this entry shall apply to services specified in sub-clauses (i), (ii) and (iii) of clause (a) of section 66D of the Finance Act, 1994:
 - Provided further that in case where continuous supply of service, as defined in clause (c) of rule 2 of the Point of Taxation Rules, 2011, is provided by the Government or a local authority, the exemption shall apply only where the gross amount charged for such service does not exceed Rs. 5000/- in a financial year;
 - 57. Services provided by Government or a local authority by way of tolerating non-performance of a contract for which consideration in the form of fines or liquidated damages is payable to the Government or the local authority under such contract;
 - 58. Services provided by Government or a local authority by way of-
 - (a) registration required under any law for the time being in force;
 - (b) testing, calibration, safety check or certification relating to protection or safety of workers, consumers or public at large, required under any law for the time being in force;
 - 59. Services provided by Government or a local authority by way of assignment of right to use natural resources to an individual farmer for the purposes of agriculture;
 - 60. Services by Government, a local authority or a governmental authority by way of any activity in relation to any function entrusted to a Panchayat under article 243G of the Constitution;
 - 61. Services provided by Government or a local authority by way of assignment of right to use any natural resource where such right to use was assigned by the Government or the local authority before the 1st April, 2016:
 - Provided that the exemption shall apply only to service tax payable on one time charge payable, in full upfront or in installments, for assignment of right to use such natural resource;
 - 62. Services provided by Government or a local authority by way of allowing a business entity to operate as a telecom service provider or use radiofrequency spectrum during the financial year 2015-16 on payment of licence fee or spectrum user charges, as the case may be;
 - 63. Services provided by Government by way of deputing officers after office hours or on holidays for inspection or container stuffing or such other duties in relation to import export cargo on payment of Merchant Overtime charges (MOT).".

Note:-The principal notification was published in the Gazette of India, Extraordinary, vide notification No. 25/2012 - Service Tax, dated the 20th June, 2012, vide number G.S.R. 467 (E), dated the 20th June, 2012 and was last amended vide notification number 09/2016 - Service Tax, dated the 1st March, 2016 vide number G.S.R. 257(E), dated the 1st March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2016

सं. 23/2016- सेवा कर

सा.का.नि. 420(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2), के उपवाक्य (क क) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एततद्वारा, सेवाकर (मूल्य निर्धारण), नियमावली 2006 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; यथा-

- 1. (1) इन नियमों को सेवाकर (मूल्य निर्धारण) संशोधन नियमावली, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।
- 2. इसके नियम 6 में, उपनियम (2) में, उपवाक्य (iv) में निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा-

''बशर्ते कि यह उपवाक्य सरकार या स्थानीय प्राधिकरण या किसी व्यापारिक निकाय द्वारा प्रदान की गई ऐसी किसी सेवा पर लागू नहीं होगा जहां कि ऐसी सेवा के लिए भुगतान को ब्याज के भुगतान या अन्य किसी प्रतिफल पर आगे के लिए टाला जा सकता है।''

> [फा. सं. 334/8/2016-टीआरयू] मोहित तिवारी. अवर सचिव

टिप्पणी:- प्रधान नियमावली अधिसूचना सं. 12/2006-सेवाकर, दिनांक 19 अप्रैल, 2006 के द्वारा, सा.का.नि. 228 (अ), दिनांक 19 अप्रैल, 2006 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 11/2014-सेवाकर, दिनांक 11 जुलाई, 2014, सा.का.नि. 480 (अ), दिनांक 11 जुलाई, 2014 के तहत, के द्वारा संशोधन किया गया है ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2016

No. 23 /2016-Service Tax

- **G.S.R. 420(E).**—In exercise of the powers conferred by clause (aa) of sub-section (2) of section 94 of the Finance Act,1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Service Tax (Determination of Value) Rules, 2006, namely:--
- 1. (1) These rules may be called the Service Tax (Determination of Value) Amendment Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In rule 6, in sub-rule (2), in clause (iv), the following proviso shall be inserted namely:-
 - "Provided that this clause shall not apply to any service provided by Government or a local authority to a business entity where payment for such service is allowed to be deferred on payment of interest or any other consideration.".

[F. No. 334/8/2016 -TRU]

MOHIT TIWARI, Under Secy.

Note:- The principal rules were published vide notification No.12/2006-Service Tax, dated the 19th April, 2006, in the Gazette of India, Extraordinary, vide number G.S.R.228 (E), dated the 19th April, 2006 and last amended by notification No.11/2014-Service Tax, dated the 11th July, 2014, vide number G.S.R.480(E),dated the 11th July, 2014.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2016

सं. 24/2016- सेवा कर

सा.का.नि. 421(अ).— वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) की धारा 94 की उपधारा (2), के उपवाक्य (क) और उपवाक्य (जजज) के तहत प्रदत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एततद्वारा, कराधान बिंदु नियम, 2011 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है; यथा

- 1. (1) इन नियमों को कराधान बिंदु (तीसरा संशोधन) नियम, 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये नियम सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।
- 2. कराधान बिंदु नियम, 2011 के नियम 7 में, तीसरे परंतुक के पश्चात, निम्नलिखित परंतुक को अंत:स्थापित किया जाएगा, यथा

"बशर्ते और भी कि सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या किसी व्यापारिक निकाय द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के मामले में कराधान का बिंदु निम्न दो तारीखों में से पहले की तारीख होगी-

- (क) जिस तारीख को ऐसी सेवा से संबंधित कोई भुगतान, अंशत: या पूर्णत:, देय होता है जैसा कि बीजक, बिल, चालान या अन्य कोई दस्तावेज जो कि सरकार या स्थानीय प्राधिकरण द्वारा जारी करके ऐसे भुगतान की मांग की गई हो, में विनिर्दिष्ट किया गा हो।
- (ख) ऐसी सेवाओं के लिए भुगतान किया जाता है।

[फा. सं. 334/8/2016-टीआरयू] मोहित तिवारी, अवर सचिव

टिप्पणी:—प्रधान नियमावली अधिसूचना सं. 18/2011-सेवाकर, दिनांक 01 मार्च, 2011 के द्वारा, सा.का.िन. 175(अ), दिनांक 01 मार्च 2011 के तहत, भारत के राजपत्र, असाधारण के भाग II, खड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 21/2016-सेवाकर, दिनांक 30 मार्च, 2016, जिसे सा.का.िन. 370(अ), दिनांक 30 मार्च, 2016 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2016

No. 24 /2016-Service Tax

G.S.R. 421(E).— In exercise of the powers conferred by clause (a) and clause (hhh) of subsection (2) of section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the Point of Taxation Rules, 2011, namely:—

- 1. (1) These rules may be called the Point of Taxation (Third Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Point of Taxation Rules, 2011, in rule 7, after the third proviso, the following proviso shall be inserted namely:-
 - "Provided also that in case of services provided by the Government or local authority to any business entity, the point of taxation shall be the earlier of the dates on which, -
 - (a) any payment, part or full, in respect of such service becomes due, as specified in the invoice, bill, challan or any other document issued by the Government or local authority demanding such payment; or
 - (b) payment for such services is made.".

Note:- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide notification No. 18/2011 – Service Tax, dated the 1st of March, 2011 vide number G.S.R. 175(E) dated the 1st of March, 2011 and last amended vide notification No. 21/2016 - Service Tax dated 30th March, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), by number G.S.R.370 (E), dated the 30th March, 2016.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 13 अप्रैल, 2016

सं. 24/2016- केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे.)

सा.का.नि. **422(अ)**.—केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1) की धारा 37 और वित्त अधिनियम 1994 (1994 का 32) की धारा 94 के तहत प्रदत्त शिक्तियों का प्रयोग करते हुए केंद्र सरकार एततद्वारा सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 में और आगे भी संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है: यथा

- 1. (1) इन नियमों को सेनवेट क्रेडिट (पांचवां संशोधन) नियमावली 2016 कहा जाएगा।
 - (2) ये सरकारी राजपत्र में अपने प्रकाशन की तारीख से प्रवर्तित होंगे।
- 2. सेनवेट क्रेडिट रूल्स, 2004 (एतश्मिन पश्चात जिसे उक्त नियमावली से संदर्भित किया गया है) में, नियम 4 में, उपनियम (7) में
 - (i) पांचवे परंतुक में ''नियम 9 के उपनियम (1) में विनिर्दिष्ट दस्तावेजों'' शब्दों के पश्चात ''सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या अन्य किसी व्यक्ति द्वारा दी गई सेवा के मामले को छोड़कर, किसी प्राकृतिक संसाधन के प्रयोग के अधिकार को देकर,'' शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।
 - (ii) छठे, सातवें और आठवें परंतुक के स्थान पर निम्निलिखित परंतुक को प्रतिस्थापित किया जाएगा:-"बशर्तें और भी कि किसी वित्तीय वर्ष में भुगतान किए गए सेवाकर पर सेनवेट क्रेडिट, जो कि पूर्ण रूप से अग्रिम या किस्तों में भुगतान किए जाने वाले एक बारगी प्रभार पर तथा सरकार, स्थानीय प्राधिकरण या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा प्राकृतिक संसाधनों के उपयोग के अधिकार को देने संबंधी सेवा के बारे में हो, 3 वर्ष की अविध तक समान रूप से देय होगा:

बशर्ते और भी कि वस्तुओं के विनिर्माता या आदान सेवा के प्रदाता, जैसी भी स्थिति हो, सरकार या अन्य कोई व्यक्ति किसी वित्तीय वर्ष में अपने को सौंपे गए अधिकार को किसी अन्य व्यक्ति को किसी प्रतिफल के एवज में देता है तो सेनवेट क्रेडिट की ऐसी बची राशि उसके द्वारा भारित ऐसे प्रतिफल पर भुगतान किए जाने वाले सेवाकर से अधिक न हो, उसी वित्तीय वर्ष के लिए अनुजेय होगा।

3. नियम 6 में, उपनियम (1) में, स्पष्टीकरण 3 में "1994" अंकों के पश्चात "बशर्ते कि ऐसे क्रियाकलापों में आदानों या आदान सेवाओं का उपयोग किया गया है" शब्दों को अंत:स्थापित किया जाएगा।

> [फा. सं. 334/8/2016-टीआरयू] मोहित तिवारी, अवर सचिव

िटप्पणी:—प्रधान नियमावली अधिसूचना सं. 23/2004-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे), दिनांक 10 सितंबर, 2004 के द्वारा, सा.का.नि. 600(अ), दिनांक 10 सितंबर, 2014 के तहत, भारत के राजपत्र, 2004 असाधारण के भाग II, खड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 23/2016-केंद्रीय उत्पाद शुल्क (गै.टे), दिनांक 01 अप्रैल, 2016, जिसे सा.का.नि. 390(अ), दिनांक 01 अप्रैल, 2016 के तहत भारत के राजपत्र में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया है।

NOTIFICATION

New Delhi, the 13th April, 2016.

No. 24/2016- Central Excise (N.T.)

G.S.R. 422(E).—In exercise of the powers conferred by section 37 of the Central Excise Act,1944 (1 of 1944) and section 94 of the Finance Act, 1994 (32 of 1994), the Central Government hereby makes the following rules further to amend the CENVAT Credit Rules, 2004, namely:-

- 1. (1) These rules may be called the CENVAT Credit (Fifth Amendment) Rules, 2016.
 - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the CENVAT Credit Rules, 2004 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 4, in sub-rule (7), -
 - (i) in the fifth proviso, after the words "documents specified in sub-rule (1) of rule 9", the words "except in case of services provided by Government, local authority or any other person, by way of assignment of right to use any natural resource" shall be inserted;
 - (ii) for the sixth, seventh and eighth proviso, the following provisos shall be substituted, namely:-

"Provided also that CENVAT Credit of Service Tax paid in a financial year, on the one-time charges payable in full upfront or in instalments, for the service of assignment of the right to use any natural resource by the Government, local authority or any other person, shall be spread evenly over a period of three years:

Provided also that where the manufacturer of goods or provider of output service, as the case may be, further assigns such right assigned to him by the Government or any other person, in any financial year, to another person against consideration, such amount of balance CENVAT credit as does not exceed the service tax payable on the consideration charged by him for such further assignment, shall be allowed in the same financial year."

3. In the said rules, in rule 6, in sub-rule (1), in *Explanation* 3, after the figures "1994", the words "provided that such activity has used inputs or input services" shall be inserted.

[F. No. 334/8/2016 -TRU] MOHIT TIWARI, Under Secy.

Note.- The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, notification No. 23/2004 - Central Excise (N.T.), dated the 10^{th} September, 2004 vide, number G.S.R. 600(E), dated the 10^{th} September, 2004 and last amended, vide, notification No. 23/2016- Central Excise (N.T.), dated the 1^{st} April, 2016 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide, number G.S.R. 390(E), dated the 1^{st} April, 2016.